भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2909

उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026 (गुरूवार)

22 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

ऊपरी असम में बाढ़-सहनीय ग्रामीण अवसंरचना

2909 **श्री तेराश गोवालाः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ऊपरी असम में बाढ़-सहनीय सामुदायिक अवसंरचना के लिए किसी समर्पित कार्यक्रम की शुरुआत करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए चिह्नित किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए पीएम-डिवाइन अथवा एनईएसआईडीएस के अंतर्गत प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सारणी क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): बाढ़ प्रबंधन की स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी उपाय, जल निकास प्रणाली विकास, समुद्र-तट कटाव-रोधी उपाय आदि से संबंधित कार्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित सभी राज्यों को सहायता देने के लिए केंद्र प्रायोजित "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" कार्यान्वित कर रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान असम में बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाओं के लिए असम सरकार को कुल 342.63 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" नामक परियोजना को सहायता प्रदान की है और यह कार्य 207 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो चुका है।

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की स्कीमों के तहत, असम में बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और नदी-तट सुरक्षा के उपायों से संबंधित 6 और परियोजनाओं के लिए 33.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, असम में आर्द्रभूमि की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने और बाढ़ एवं कटाव के जोखिम को कम करने के लिए एनईएसएसी द्वारा चिन्हित लगभग 5,900 वर्ग किमी और असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा प्रलेखित 3,500 वर्ग किमी की आर्द्रभूमि के जीर्णोद्धार और बहाली का कार्य किया गया है।

*****